1	2	3	4	5	6
6.	Jharkhand	1467.25	42.06	0.40	—
7.	Karnataka	1562.85	221.46	2.00	61.66
8.	Kerala@	—	—	—	55.60
9.	Madhya Pradesh	790.38	125.89	1.00	51.78
10.	Maharashtra	1730.61	20.00	—	129.99
11.	Orissa	871.40	120.18	2.00	90.52
12.	Punjab	3529.44	125.41	—	101.47
13.	Rajasthan	7519.76	207.68	7.00	171.16
14.	Tamil Nadu	1545.76	228.30	0.50	84.87
15.	Uttaranchal	401.81	10.62	0.50	13.38
16.	Uttar Pradesh	7539.79	481.10	2.00	120.95
17.	West Bengal	—	—	—	41.80

* For the whole year.

** First instalment till middle of January after making allowance for available balance in the Calamity Relief Fund(CRF) i.e. these amounts will be reduced to the extent States have balances in the CRF to deal with the drought.

@ Not indicated.

Additional relief to rain-deficient States

†*70. SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY:††
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether nine-rain-deficient States have sought Rs.16,741.96 crore additional relief from the Centre;

(b) if so, whether these States have sought relief from Natural Calamity Contingency Fund;

† Starred Question Nos. 62, 66 and 70 were taken together.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ravula Chandra Sekar Reddy.

(c) whether this demand is in addition to the second instalment of Rs.809 crore already released; and

(d) if so, to what extent the demand of these States for additional relief from NCCF has been accepted by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HUKUMDEO NARAYAN YADAV): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) States have already been sanctioned both instalments of Central share of the Calamity Relief Fund (CRF) including advance release of the second instalment, amounting to total of Rs. 1227.29 crores. Further, the High Level Committee (HLC) has approved an amount of Rs. 1999.14 crores, subject to adjustment of balances in the CRF of the States, as per the following details:

(Rs. in crores)

S. No.	State	Assistance demanded	Assistance found admissible subject to adjustment of CRF balances.
1.	Andhra Pradesh	1210.90	174.61
2.	Chhattisgarh	880.66	92.73
3.	Haryana	1895.98	109.65
4.	Himachal Pradesh	155.86	39.45
5.	Jammu & Kashmir	1623.98	—
6.	Jharkhand	1467.25	42.06
7.	Karnataka	1562.85	221.46
8.	Madhya Pradesh	790.38	125.89
9.	Maharasbtra	1730.61	20.00
10.	Orissa	871.40	120.18
11.	Punjab	3529.44	125.41
12.	Rajasthan	7519.76	207.68
13.	Tamil Nadu	1545.76	228.30
14.	Uttaranchal	401.81	10.62
15.	Uttar Pradesh	7539.79	481.10

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, देश में अकाल की भीषण स्थिति कई राज्यों के अंदर बनी हुई है। राजस्थान जैसे राज्य के अंदर तो सदियों से ऐसा अकाल नहीं पड़ा है जैसा अकाल अब पड़ा है। इसकी सूचना केन्द्र सरकार को थी और राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय आपदा कोष से आकस्मिक सहायता के लिए केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया। राज्य सरकार ने ज्ञापन बहुत पहले ही, जुलाई के महीने में ही दे दिया था कि इस वर्ष वर्षा कम हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष मानसून कम आने की, वर्षा कम होने के कारण यह संभावना बन गई थी कि इस साल भयंकर अकाल पड़ेगा। इस प्राकृतिक आपदा से लोगों को राहत दिलाने के लिए आपने क्या आकस्मिक योजना बनाई?

मेरे प्रश्न का ''ख'' भाग यह है कि केन्द्रीय दल आपने राज्यों के दौरे के लिए भेजे। ये केन्द्रीय दल कब-कब, किस-किस राज्य में भेजे और केन्द्रीय दलों ने किस-किस राज्य को कितना नुकसान हुआ है, कितनी क्षति हुई है, इसके बारे में बताया।

श्री सभापति: यह तो प्रश्न के उत्तर में बता दिया है। यह तो मूल प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया होगा।

श्री मूल चन्द मीणा: सर, यह आनसर में कहीं नहीं है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि किस-किस राज्य में कितना नुकसान हुआ है? केन्द्रीय दल की रिपोर्ट कितने दिन के बाद आई और उस पर आपने तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की? पैसा और अनाज रिलीज करने के लिए हुई देरी का कारण क्या है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री सभापति: मैं प्रश्न संख्या 62, 66 और 70 को क्लब करता हूं। ये सब एक ही नेचर के हैं। मंत्री जी इनका एक साथ जवाब दे दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि सूखे से संबंधित मंत्रालय....(**व्यवधान**)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The Chairman has clubbed these three questions. But you have replied only to Question No. 62. First, you reply to the other two questions, and then the supplementary questions.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति महोदय, बाकी जितने प्रश्न हैं, उन सब के उत्तर मैं सभा पटल पर रखता हूं। महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल पांच घंटे तक सूखे वाले विषय पर इस सदन में माननीय सदस्यों ने चर्चा की है और उसका उत्तर आज माननीय मंत्री जी देने वाले हैं। कल इस विषय पर पूरी चर्चा हुई थी, लेकिन यह प्रश्न आया है....(व्यवधान)....

श्री सभापति: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: जहां तक सूखे का सवाल है, सूखे के संबंध में राज्य सरकारों से जो प्रतिवेदन हमारे पास आते हैं, तो जो हमारे ज्वाइंट सैक्रेटरी जो क्षेत्रीय अधिकारी के तौर पर काम करते हैं वह प्राथमिक तौर पर जाकर उसका मुआयना करते हैं और जब हमारे क्षेत्रीय अधिकारी, ज्वाइंट सैक्रेटरी वहां जाते हैं, तो जहां से भी हमारे पास प्रतिवेदन आए थे, उनके संबंध में अगस्त 2002 तक क्षेत्रीय अधिकारियों ने मुआयना करके अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसके बाद केन्द्रीय टीम को हमने भेजा था और जो छूटे हुए कुछ राज्य थे, जिन्होंने प्रतिवेदन दिया था, सितम्बर-अक्तूबर तक सभी राज्यों से केन्द्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उनके प्रतिवेदन आने के बाद फिर अंतर्मंत्रालीय समूह की जो बैठक होती है, जिसमें कृषि मंत्रालय, सहकारिता के सचिव उसके अध्यक्ष होते हैं, और मंत्रालय के सचिव उसके सदस्य होते हैं। उस अंतर्मंत्रालीय समूह के प्रतिवदेन पर हमारी जो समिति है, माननीय उप प्रधान मंत्री जी जिसके अध्यक्ष हैं, अंतर्मंत्रलीयस्तर पर उसका निर्णय होता है और यही हमारी प्रक्रिया है। इसलिए हमारे पास जिन राज्यों से प्रतिवेदन आए हैं, उस आधार पर, उनकी मांगों के आधार पर सभी राज्यों को राहत देने की व्यवस्था की है।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, वहां पर कितनी क्षति हुई है। ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: श्री नटवर सिंह जी।

श्री मूल चन्द मीणा: महोदय, अभी मुझे दूसरा सप्लीमेंटरी भी पूछना है किन्तु मेरे पहले प्रश्न का जवाब ही माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। मैंने यह पूछा था कि किन-किन राज्यों में कितना नुकसान हुआ है और किन-किन राज्यों की रिपोर्ट पर क्या विचार हुआ है और उसमें इतनी देरी क्यों हुई है? यह मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी ने इस संबंध में कुछ नहीं बताया है।

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ करैक्शन है। क्योंकि क्वेश्चन ऑवर में मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठा सकता इसलिए प्वाइंट ऑफ करैक्शन है। महोदय, मेरे पास सारे राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के पत्र उपलब्ध हैं। उन्होंने जितनी मांग खाद्यान्न की की है और जितनी राशि की मांग की है, उतनी उन्हें प्रदान नहीं की गयी है। मैं मान्यवर आपसे संरक्षण चाहूंगा और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि जितनी मांग थी, वह पूरी कर दी गयी है, वह भ्रमित करने वाला है।

श्री सभापति: मैं आपको बता दूं कि यह मांग हर साल होती है और किसी भी सरकार ने जितनी मांग की गयी है, उसकी कभी पूर्ति नहीं की।

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, यह सही है लेकिन माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि उनकी मांग पूरी हो गयी है, उसे मैं करैक्ट कर रहा हूं।

श्री सभापति: जो कुछ यह बता रहे हैं, उस पर आप संतोष करिए। मिनिस्ट्रीयल कमेटी इस पर बात कर रही है। बात करने के बाद जिसको जितने साधन चाहिए और जितने साधन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उपलब्ध करा सकती है, निश्चित रूप से कराएगी।

श्री मूल चन्द मीणा: महोदय, सूखा राहत सहायता के लिए केन्द्र सरकार जिस तरह से भेदभाव कर रही है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक आपने जिस जिस राज्य को जितनी राशि उपलब्ध कराई है, उसके कोई मापदंड भी होंगे। राजस्थान सबसे ज्यादा भंयकर और भीषण अकाल की स्थिति में है, अन्य किसी राज्य में इतना भीषण अकाल नही पड़ा है किन्तु राजस्थान के प्रति आपका दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण लगता है। कृपया आप वह मापदंड बताएं क्योंकि दूसरे राज्यों को आपने राजस्थान के बजाए ज्यादा सहायता दी है। इसके क्या कारण हैं?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: राज्य सरकारों की तरफ से जो हमारे पास मांग आती है.....

श्री मूल चन्द मीणा: इसके अलावा कृपया यह भी बताएं कि राजस्थान सरकार ने 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं मांगा था और उन्हें दो लाख मीट्रिक टन गेहूं दिया गया है, इसका क्या आधार है?

श्री सभापति: अब आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान सरकार की तरफ से हमारे पास जो मांग की गयी थी, उसमें हमने उन्हें सात लाख टन अनाज भेजा है। उन्होंने

56 लाख टन की मांग की थी। हमारी सैंटर टीम ने 6 लाख पचास हजार टन की सिफारिश की थी लेकिन उसके बावजूद भी माननीय उप प्रधान मंत्री जी के साथ जो कमेटी है, उस हाई लैवल कमेटी की सिफारिश पर सात लाख टन अनाज अब तक राजस्थान को हमने मुहैया करा दिया है। उसके अलावा भी राजस्थान को सूखे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से जितनी मदद दी गयी है, अन्य राज्यों को उतनी सुविधा नहीं दी गयी है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Minister, will you please tell me date on which you had sent the letter mentioning that seven lakh metric tonnes of foodgrains have been sanctioned to the State Government of Rajasthan?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: यह डेट जनवरी तक....जो हमें 7 लाख मीट्रिक टन इनको देना है, उसमें से 2 लाख मीट्रिक टन हमने दे दिया था और 5 लाख मीट्रिक टन राजस्थान को और अधिक देने की स्वीकृति हमने दे दी है।....(**व्यवधान**)...

श्री मोती लाल वोरा: कब दिया?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: राजस्थान सरकार से हमको युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट जैसे-जैसे दिया जाएगा, वैसे-वैसे हम उनको अनाज देते जाएंगे।....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक मिनट....एक मिनट...देखिए, 5 लाख मीट्रिक टन अनाज राजस्थान के लिए स्वीकृत हुआ है।.....(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं कि 16.11.2002 को यह मीटिंग हुई, उसमें यह तय हुआ। माननीय मंत्री जी अपना रिकॉर्ड देख लें, माननीय मंत्री जी को में सरकारी रिकॉर्ड की तिथि बता रहा हूं।

श्री सभापति: कोई रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन टास्क फोर्स की बैठक हुई...(**व्यवधान**)....

श्री सुरेश पचौरी: नहीं सर, ये गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, 16 नवम्बर को केन्द्र सरकार ने 5 लाख मीट्रिक टन रिलीज़ करने का आदेश दे दिया है। अब यह राजस्थान सरकार के ऊपर है कि वह कितनी जल्दी उठाए और वितरित करे।

श्री सभापति: ठीक है।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Mr. Chairman, Sir, after the Central Team visited the State of Andhra Pradesh, we expected more funds from the Government of India. The State Government of Andhra Pradesh had demanded Rs. 1210 crores, as relief, from the Government of India, but I am sorry to say that we have received only Rs. 174 crores, and no amount has been released under the Rural Water Supply Programme. I would like to know from the hon. Minister whether there is any programme with the Government of India to tackle the drinking water problem in the country, and, more particularly, in Andhra Pradesh. Will the hon. Minister consider the request of the State Government of Andhra Pradesh and allocate special funds for tackling the drinking water problem under the Rural Water Supply Programme?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, आंध्र सरकार से 1210 करोड़ रुपए की मांग की गई थी जिसमें हाई लेवल कमेटी ने 174.61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और अब तक आंध्र प्रदेश को जो पैसे हमने रिलीज़ किए हैं, वे 81 करोड़ 88 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 81 करोड़ 88 लाख सेकेंड इंस्टॉलमेंट के रूप में हैं। यह राशि हमने आंध्र सरकार को दे दी है और जहां तक.....(व्यवधान)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: The hon. Member said that out of Rs. 1210 crores, you have sanctioned Rs. 174 crores only. He is asking for more funds. Whatever information you are giving, he is aware of that.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: जहां तक पेयजल का उन्होंने प्रश्न किया है, 2000-2001 में 116 करोड़, 2001-2002 में 136 करोड़ और 2002-2003 में 134.77 करोड़ पेयजल के मामले में आंध्र सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा राशि दी गई है।

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, देखिए....(व्यवधान)...एक मिनट...बैठिए आप। ...(व्यवधान)....लालू जी, थोड़ा सुन लीजिए। आप तो कुल बैठे थे, जिस समय ड्राउट सिचुएशन पर यहां चर्चा हुई, उस समय इस सदन में उपस्थिति बहुत कम थी। आज जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि कल उन्होंने इसी आधार पर अपना भाषण दिया होता तो उसका ज्यादा प्रभाव रहता। सरकार भी उसको गंभीरता से लेती। आज एक क्वेश्चन को हम ड्रैग करते जाएंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय का जो उत्तर हो, उसमें आप कोई क्लेरिफिकेशन चाहें तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ता हूं।

श्री लालू प्रसाद: सर, जो छोटे-छोटे दल यहां हाज़िर रहते हैं, उनका टाईम बहुत कम रहता है। बड़े दल तो हाज़िर नहीं रहते हैं इसलिए उनके टाईम में कटौती करके छोटे दलों को दे दें तो हम लोग बैठे रहेंगे।

श्री सभापति: कल तो मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि सभी मैम्बर्स, चाहे वे किसी भी दल के हों, ज्यादा से ज्यादा इस डिबेट में भाग लें लेकिन उस समय किसी ने भाग नहीं लिया और क्या एक रात में ही इतना अकाल पड़ गया कि इतने प्रश्न खड़े हो गए? यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)... मेरी सुन लीजिए...(व्यवधान)....

SHRI V.V. RAGHAVAN: Sir, the State of Kerala is not included in the list of drought-affected States, which has been prepared by the Union Government. It is one of the worst hit States. It is not only worst hit, but cash crops have also failed there. And, there is no financial help from the Central Government. No drought relief and other measures are being undertaken by the Central Government.

श्री सभापति: आप बताइए, आप कल कहां थे?....(व्यवधान)...

SHRI V.V. RAGHAVAN: Sir, yesterday, I was not present in the House when the discussion on drought took place.

MR. CHAIRMAN: So, you have missed the chance.

SHRI V.V. RAGHAVAN: Sir, the Question No. 62 is about drought. So, I want to put one supplementary. The hon. Minister...

MR. CHAIRMAN: No; Question No. 63.

Export of medicinal plants

*63. SHRIMATI N. P. DURGA:†
DR. ALLADI P. RAJKUMAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what bottlenecks India is facing in playing a major role in the supply of medicinal and herbal plants for the global herbal medicine and cosmetics industry; and

(b) the agencies involved in encouraging farmers to use latest technological developments for better and quicker yields of such plants and selling the produce in the global market?

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati N.P. Durga.